Serving Education for Last 40 Years

NEERAJ®

M.P.S. -2

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध : सिद्धांत एवं समस्याएँ

(International Relations: Theory and Problems)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Dr. Subodh Jha & Dr. Sanjay Kumar Shrivastav*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 420/-

Content

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध : सिद्धांत एवं समस्याएँ

(International Relations: Theory and Problems)

Question Paper—June-2024 (Solved) 1-4

Question Paper—December-2023 (Solved) 1

Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2

Question Paper—December-2022 (Solved) 1

Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1-2

Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) 1-2

Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1

Question Paper—December, 2019 (Solved) 1-2

Question Paper—June, 2019 (Solved) 1-2

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
1.	यथार्थवादी एवं नव-यथार्थवादी उपागम (Realist and Neo-Realist Approaches)	1
2.	उदारवादी एवं नव-उदारवादी उपागम (Liberal and Neo-Liberal Approaches)	13
3.	मार्क्सवादी तथा अन्य विप्लववादी उपागम (Marxist and Other Radical Approaches)	20
4.	नव-विप्लववादी उपागम (Neo-Radical Approaches)	27
5.	उत्तर-संरचनावादी तथा उत्तर-आधुनिकतावादी उपागम (Post-Structuralist and Post-Modernist Approaches)	32
6.	महिलावादी उपागम (Feminist Approaches)	36

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

7. पर्यावरणवादी उपागम (Environmental Approaches) 44

8. एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका की विश्वदृष्टि 54
(Worldviews from Asia, Africa and Latin America)

9. शीत-युद्ध का अंत (End of Cold-War) 63

10. शीत-युद्धोत्तर मुद्दे (Post-Cold-War Issues) 78

11. उभरती शक्तियाँ (Emerging Powers) 88

12. क्षेत्रीय समूह (Regional Groupings) 93

13. भूमंडलीकरण (वैश्वीकरण) (Globalisation) 104

14. अन्तर्राष्ट्रीय असाम्यताएँ (International Inequities) 114

15. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के तत्त्व 126
(Elements of International Economic Relations)

16. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रबन्धन 138
(Management of International Relations)

17. नवीन वैश्वी (भूमंडलीय) वैश्विक व्यवस्था में भारत 147
(India in the New Global Order)

18. आत्मनिर्णय का अधिकार (Right to Self-determination) 155

19. हस्तक्षेप/आक्रमण (Intervention/Invasion) 160

20. परमाणु प्रसार (Nuclear Proliferation) 170

21. अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद (International Terrorism) 181

22. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका 191
(Role of Science and Technology in International Relations)

23. राष्ट्रों के बीच असमानता 198
(Inequality among Nations)

24. विश्वव्यापी भूमंडलीय निगमवाद और राज्य प्रभुसत्ता 204
(Global Corporatism and State Sovereignty)

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

25. मानव अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 211
(Human Rights and International Trade)

26. अमेरिकी शक्ति का परिवर्तनशील स्वरूप 225
(Changing Nature of American Power)

27. चीन : एक उभरती हुई शक्ति (China as an Emerging Power) 232

28. केन्द्रीय एशियाई गणतंत्रों का आविर्भाव 237
(Emergence of Central Asian Republics)

29. संजातीय पुनरुत्थान और 'पहचान' युद्ध 241
(Ethnic Resurgence and 'Identity' Wars)

30. आदिवासी/मूलवासी आंदोलन संरचना 246
(Aboriginal/Indigenous Movements)

31. जनसंख्या विस्थापन : राज्यांतरिक और अंतर्राज्य 252
(Displacement of Population: Intra-state and Inter-state)

32. पार-राष्ट्रीय आंदोलन : सांस्कृतिक और सभ्यतामूलक 260
(Transitional Movements: Cultural and Civilisational)

33. गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका (Role of NGOs) 265

34. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय की अवधारणा 274
(Concept of Justice in International Relations)

35. मानव सुरक्षा (Human Security) 279

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध : सिद्धांत और समस्याएँ

(International Relations: Theory and Problems)

M.P.S.-2

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. उदारीकरण की अंतर्निहित मान्यताओं की जाँच कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-2, पृष्ठ-13, 'अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के अध्ययन का उदारवादी उपागम'

प्रश्न 2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का औचित्य सिद्ध कीजिए।

उत्तर–संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संयुक्त राष्ट्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। परिषद में 5 स्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। वैश्वीकरण के पश्चात् भू-राजनीतिक संरचना में काफी परिवर्तन आने से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठती रही है। वर्तमान में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के प्रवल दावेदार के रूप में देखा जाता है।

भारत पिछले कई वर्षों से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए अपनी स्थायी सदस्यता के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह विश्व की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय क्षेत्र से लेकर पीस कीपिंग अभियानों तक भारत की उल्लेखनीय भूमिका रही है। भारत की सदस्यता के लिए फ्रांस सहित कई देशों का समर्थन भी प्राप्त है। इन तमाम दावेदारियों के बावजूद भारत की सदस्यता प्राप्ति के समक्ष निम्नलिखित बाधाएँ हैं-

भारत की सदस्यता के लिए चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए स्थायी सदस्यों के साथ-साथ दो-तिहाई देशों द्वारा पुष्टि करना आवश्यक है।

चीन भारत की सदस्यता का विरोध करता है। यद्यपि अमेरिका भारत की सदस्यता का समर्थन करता है, लेकिन वीटो पावर सहित सदस्यता के पक्ष में नहीं है।

भारत की आर्थिक-सामाजिक स्थिति ज्यादा सुदृढ़ नहीं है। विभिन्न वैश्विक सूचकांकों जैसे–वैश्विक भूख सूचकांक, मानव विकास सूचकांक आदि में भारत का स्थान काफी पीछे है। कोफी अन्नान समूह के सदस्य देशों द्वारा भारत का विरोध।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) तथा संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट (यूएजीसी) से प्रस्ताव को अलग-अलग पास करवाना।

सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अन्य दावेदारों का होना।

सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से भारत को लाभ–

1. भारत महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे और नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा पाएगा।

2. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।

3. भारत की उभरती हुई सुपर पावर की छवि को बढ़ावा मिलेगा।

4. पीओके तथा ब्लूचिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान पर मजबूत पकड़ बनाने में सक्षम हो पाएगा।

5. देश का सामाजिक-आर्थिक विकास कर पाएगा।

सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के पक्ष में तर्क–1.3 बिलियन आबादी के साथ भारत, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहां विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 1/5वाँ हिस्सा निवास करता है। भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक कद ने भारत के दावों को और मजबूत किया है। मौजूदा समय में भारत विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा पीपीपी पर आधारित जीडीपी की दृष्टि से भारत विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत को अब विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स और जी-20 जैसे आर्थिक संगठनों में सबसे प्रभावशाली देशों में गिना जाता है। भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक रूप से विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली रही है।

भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रबल दावेदार है। इसे प्रमुख देशों का समर्थन भी प्राप्त है, लेकिन चीन सहित

NEERAJ PUBLICATIONS

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध : सिद्धांत और समस्याएँ

(International Relations: Theory and Problems)

M.P.S.-2

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *प्रत्येक भाग से कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग - I

प्रश्न 1. राज्य के नारीवादी दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए उसकी प्रासंगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-6, पृष्ठ-37, 'राज्य का महिलावादी विचार'

प्रश्न 2. अल्पविकास विकास से किस प्रकार भिन्न है? अल्पविकास के सिद्धांत की मूलभूत विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-4, पृष्ठ-27, 'अल्पविकास का सिद्धांत', 'अल्पविकास के सिद्धान्त की उत्पत्ति' तथा पृष्ठ-30, प्रश्न 2

प्रश्न 3. वैश्विक पर्यावरण संकट पर उत्तर-दक्षिण विभाजन की जाँच कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-7, पृष्ठ-51, 'उत्तर-दक्षिण विभाजन'

प्रश्न 4. क्षेत्रीय सहयोग के लिए एशियाई और अफ्रीकी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-56, 'अखिल एशियावाद', पृष्ठ-57, 'अफ्रीका की एकता'

प्रश्न 5. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए शीत युद्ध के बाद की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-86, प्रश्न 3 तथा पृष्ठ-87, प्रश्न 5

भाग - II

प्रश्न 6. हस्तक्षेप से क्या तात्पर्य है? हस्तक्षेप की तीन अलग-अलग किस्मों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-19, पृष्ठ-168, प्रश्न 1, पृष्ठ-169, प्रश्न 2 तथा प्रश्न 3

प्रश्न 7. सीमापार आतंकवाद से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कैसे भिन्न है? उदाहरण के साथ समझाइए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-21, पृष्ठ-182, 'सीमापार आतंकवाद', 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद', पृष्ठ-189, प्रश्न 1

प्रश्न 8. शक्ति के विश्व पदानुक्रम में यू.एस. की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-26, पृष्ठ-225, 'विश्व शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय' तथा पृष्ठ-230, प्रश्न 2

प्रश्न 9. डायस्पोरा का क्या अर्थ है? यह पारराष्ट्रीय आन्दोलनों को कैसे बढ़ावा देता है?

उत्तर–डायस्पोरा का अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है, जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार चले जाते हैं और नए-नए देशों में बस जाते हैं तथा वहां सामाजिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उस राष्ट्र से संबंध बनाए रखते हैं, जिसके वे मूल निवासी हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी पारराष्ट्रीय सामाजिक क्षेत्र में रहते हैं। यद्यपि समुदाय अपने घर या देश से बाहर चले जाते हैं फिर भी डायस्पोरा संबंध बनाए रखते हैं।

इसे भी देखें–संदर्भ–अध्याय-32, पृष्ठ-260, 'पार-राष्ट्रीय स्थानांतरणों का अभिप्राय', पृष्ठ-263, 'पार-राष्ट्रीय समुदाय और सभ्यतामूलक आंदोलन'

प्रश्न 10. 'नृजातीयता' शब्द की व्याख्या कीजिए। युद्ध के बाद के वर्षों में नृजातीय आन्दोलनों में वृद्धि के कारणों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-29, पृष्ठ-244, प्रश्न 1, पृष्ठ-242, आधुनिकीकरण और संजातीय पुनरुत्थान और संघर्ष, तर्कहीन सीमाएं : राज्य प्रणाली की चुनौती' तथा पृष्ठ-243, आधुनिक राज्य की हस्तक्षेपवादी भूमिका और परंपरागत स्वायत्तता की क्षति', पृष्ठ-244, 'पहचान के लिए युद्ध', पहचान के लिए युद्ध के कारण'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध : सिद्धांत एवं समस्याएँ
(International Relations: Theory and Problems)

यथार्थवादी एवं नव-यथार्थवादी उपागम
(Realist and Neo-Realist Aproaches)

1

NEERAJ PUBLICATIONS

प्रस्तावना

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध की सर्वांगीण विवेचना के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाये गये हैं, उनमें यथार्थवादी उपागम प्रमुख स्थान रखता है। अठाहरवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में यथार्थवादी दर्शन को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति समझने की कुंजी माना जाता था, तथापि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इसका पुनरुत्थान द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद हुआ। मुसोलिनी और हिटलर के उदय, उनकी विस्तारवादी आक्रामक अभिवृत्तियाँ, उनके द्वारा शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर जोर देना, आदि ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों को मानव स्वभाव एवं विश्व राजनीति की यथार्थता को समझने के लिए प्रेरित किया।

श्री जॉर्ज केनन और राइनॉल्ड नेबुर जैसे अनेक विद्वानों ने यथार्थवाद के विकास में योगदान दिया पर इसे सैद्धान्तिक आधार प्रदान करने का श्रेय श्री मॉरगेन्थाउ को दिया जाता है क्योंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण को एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में मॉरगेन्थाउ ने ही परिणत किया। फलत: यथार्थवाद के अन्तर्गत हम जब कभी अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचार करते हैं तो मॉरगेन्थाउ का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाता है। मॉरगेन्थाउ केवल यथार्थवादी लेखक ही नहीं बल्कि पहले सिद्धान्तकार हैं जिन्होंने यथार्थवादी साँचे को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया। यथार्थवादी दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी-न-किसी रूप में वैमनस्य, संघर्ष आदि मौजूद रहता है अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय समाजों में शक्ति अथवा प्रभाव की प्रतिस्पर्धा सदैव चलती रहती है और किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय कानून अथवा संस्था द्वारा इस संघर्षात्मक स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अत: कूटनीति का प्रमुख कार्य यही है कि शक्ति प्रतिस्पर्धा पर किसी-न-किसी रूप में अंकुश लगाया जाये। दूसरे शब्दों में, यथार्थवाद विरोध एवं संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शाश्वत तत्त्व के रूप में देखता है, एक ऐसे तत्त्व के रूप में जिसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए कूटनीति की मुख्य चुनौती यही है कि ऐसे साधनों को विकसित किया जाए ताकि शक्ति संघर्षों में सफलता हासिल की जा सके।

यथार्थवाद क्या है?

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का अर्थ न तो प्लेटो वाला वह मत है जो अमूर्त विचारों को यथार्थ मानता है और न वह तात्कालिक लाभ का राजनीतिक सिद्धान्त है जिसे अक्सर मैक्यावेली का सिद्धान्त कहा जाता है। यथार्थवाद जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित अनुभववाद का दार्शनिक विचार भी नहीं है। यह कहना अधिक उचित होगा कि यथार्थवाद विचारों का समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों के निहितार्थों को अपनी चिन्तन सामग्री मानता है। इन विचारों का जन्म व्यक्ति के इस विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं और इसलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने को तैयार रहना चाहिए। अत: यथार्थवादी दृष्टिकोण की बुनियादी मान्यता यह है कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं यानी यथार्थवादी विरोध एवं संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं न कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की आकस्मिक घटना के रूप में। इसलिए

www.neerajbooks.com

उनका मानना है कि राजनय और राष्ट्र नेतृत्व का मुख्य कार्य शक्ति की होड़ में विजय प्राप्त करना है और यह तभी सम्भव है जब शक्ति संतुलन हमेशा अपने पक्ष में बनाये रखने का प्रयास किया जाए। यथार्थवाद शक्ति संघर्ष के स्थायित्व और उसकी सर्वव्यापकता को अपना मार्गदर्शक मानता है तथा राष्ट्र-राज्य पर मुख्य रूप से ध्यान देता है अर्थात् राष्ट्रहित की महत्ता पर इसमें विशेष जोर दिया जाता है। इस दृष्टिकोण की यह भी मान्यता है कि शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रहित की रक्षा की जा सकती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्रबिन्दु मानता है, इसलिए इसे शक्ति का दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्रों की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शक्ति और हित के आधार पर ही राजनीति के वास्तविक अभिनेताओं के कार्यों को समझा जा सकता है। यथार्थवाद इस बात पर भी बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिये जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धान्तों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर।

एक यथार्थवाद या अनेक?

विद्वानों में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध की यथार्थवाद की सीमाओं को लेकर मत भिन्नता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह राष्ट्रों के व्यवहार का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ तत्त्वों की आंशिक व्याख्या करता है, यह पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सच्चाई की पूर्ण व्याख्या नहीं करता। इसके बावजूद अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषणकर्त्ताओं ने यथार्थवादी विचारधारा को दो मुख्य वर्गों में रखा है, जिसमें प्रथम प्राचीन (परम्परागत) यथार्थवाद है तथा दूसरा समकालीन या आधुनिक यथार्थवाद अर्थात् नव-यथार्थवाद है।

प्राचीन (परम्परागत) यथार्थवाद

प्राचीन (परम्परागत) यथार्थवाद यह मानता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में आवश्यक तौर पर शक्ति संघर्ष का रूप अपना लेती है। इस यथार्थवादी दृष्टिकोण को एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में परिणत करने हेतु अनेक विद्वानों, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने कई शताब्दियों तक अपना योगदान दिया। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्थित तथा विस्तृत सिद्धान्त के रूप में इसकी उत्पत्ति एवं लोकप्रियता द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद के काल में हुई। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी प्रतिमान का निर्माण करने का श्रेय हान्स जे. मॉरगेन्थाउ को प्राप्त है। हान्स जे. मॉरगेन्थाउ ने ही अपनी पुस्तक *'पॉलिटिक्स एमंग नेशन्स'* (Politics among Nations) में यथार्थवादी दृष्टिकोण को एक विशिष्ट रूप प्रदान किया। पॉलिटिक्स एमंग नेशन्स (Politics among Nations) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसका निर्माण सैद्धांतिक (Theoretical) पृष्ठभूमि के आधार पर हुआ है। इस यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव स्वभाव में निहित अन्तर्विरोधों के कारण शुद्ध नैतिक मान्यताओं पर विश्व समाज का संचालन पूर्णतया असंभव है। वे मानते हैं कि विश्व के राष्ट्रों के बीच किसी न किसी रूप में वैमनस्य, संघर्ष आदि मौजूद रहता है अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय समाजों में शक्ति अथवा प्रभाव की प्रतिस्पर्धा सदैव चलती रहती है। अत: राजनेता का कौशल यही है कि ऐसे साधनों को विकसित किया जाये ताकि शक्ति संघर्षों में अपने राष्ट्रहित की महत्ता पर बल देते हुए शक्ति प्रतिस्पर्धा में सफलता हासिल की जा सके।

मॉरगेन्थाउ ने अपने मॉडल में शक्ति (Power) पर मुख्य रूप से बल दिया। उनकी मान्यता है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा है। शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रहित की महत्ता पर बल देने के फलस्वरूप इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी बन जाता है। मॉरगेन्थाउ के शब्दों में, उनका सिद्धान्त यथार्थवादी इसलिए है कि वह मानव स्वभाव को उसके यथार्थ में देखते हैं जो इतिहास में अनादिकाल से बार-बार परिलक्षित हो रहा है।

यह वह समय था जब प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व ट्रॉटस्की, नीत्से तथा एरिक कॉपसन आदि विचारकों ने भी शक्ति के इस दृष्टिकोण पर बल दिया। इन्होंने शक्ति प्रदर्शन को राज्य की विशेषताएँ माना। हैराल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन जैसे विद्वानों ने भी शक्ति की संकल्पना को समकालीन राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना माना। इनके अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति वितरण करना और शक्ति का उपयोग करना। सन् 1945 के बाद के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने जिनमें ई.एच. कार, मॉरगेन्थाउ आदि प्रमुख थे, ने राजनीति विज्ञान की इस शक्ति संकल्पना को विस्तृत करके अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर लागू करने का प्रयास भी किया।

वस्तुत: यथार्थवादियों का ध्येय राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार मात्र माना जाता था और इसलिए उनकी नीतियाँ शान्ति-विरोधी समझी जाने लगीं, क्योंकि यथार्थवादी यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न साध्य है या साधन। कभी-कभी यर्थाथवादी स्वयं यह मानने लगते हैं कि राज्य सदैव अपनी शक्ति बढ़ाने के यत्न में लगे रहते हैं। अपने इस दावे को यथोचित ठहराने के लिए वे कहते हैं कि शक्ति सर्वोच्च मूल्य या प्राप्ति योग्य आदर्श है, जिसे पाने के लिए राज्य प्रयासरत रहते हैं। दूसरा यह शक्ति या प्रभुत्व राष्ट्रीय हित के सम्वर्द्धन का एकमात्र साधन मानता है। जिस सीमा तक यह दृष्टिकोण शक्ति पर जोर देता है उस सीमा तक इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। शक्ति के अध्ययन पर जोर देते हुए हान्स जे. मॉरगेन्थाउ ने स्वयं लिखा है कि "International

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

politics, like all politics is a struggle for power, whatever the ultimate aims of international politics, power is the immediate aim."

लेकिन द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर तथा काफी तीव्रता से यथार्थवाद में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक परिवर्तन हुए तथा 20वीं सदी के अन्तिम दो दशकों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कई गुणात्मक परिवर्तन आये। शीत-युद्ध, रूस तथा अमेरिका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास तथा रूस, यूरोप तथा दुनिया के अन्य भागों में हुए परिवर्तनों, शस्त्र-नियंत्रण के प्रयास तथा कई अन्य ऐसे परिवर्तनों ने यथार्थवादी दृष्टिकोण के स्वरूप को काफी भिन्न बना दिया। ऐसे ही परिवर्तन के दौर में यथार्थवादी सिद्धान्त ने विकास की दिशा में प्रगति की और कदम बढ़ाया और समकालीन यथार्थवाद या नव-यथार्थवाद का प्रस्फुटन हुआ।

समकालीन या आधुनिक यथार्थवाद या नव-यथार्थवाद

समकालीन या आधुनिक यथार्थवाद के उद्भव में वैसे तो क्विंसी राइट (Quincy Wright), स्पराउट (Sprout) आदि अन्य लेखकों का भी योगदान है लेकिन एक क्रमबद्ध विचारधारा के रूप में इसे महत्त्वपूर्ण बनाने का श्रेय कैन्निथ वाल्ट्ज (Kenneth Waltz) को दिया जाता है। कैन्निथ वाल्ट्ज कहते हैं कि *"सभी राज्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तथा सभी को ऐसा करना भी चाहिए। एक राष्ट्र हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखना तथा सुरक्षित रखना चाहता है और यही उसे करना भी चाहिए।"* (A nation always seeks to maintain and secure its national interest and this is what it should do.) क्या इसका अर्थ यह है कि जो एक राष्ट्र कर रहा है उसे वही करते जाना चाहिए, इसलिए संरचनात्मक परिवर्तन यथार्थवाद में आवश्यक हो गया। उनका मानना था कि एक विशेष रूप में मानवीय स्वभाव को परिभाषित करना, फिर उसे ही तर्कों का आधार मानने के लिए कहना, वास्तव में आदर्शवाद है न कि यथार्थवाद।

दसअसल 1945 के बाद एक ओर तो विज्ञान और प्रोद्योगिकी के आगमन से दुनिया बहुत छोटी हो गई और दूसरी ओर इससे युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। दुनिया छोटी हो जाने से सहयोग की क्षमता का उपयोग करने की ओर संसार का ध्यान गया और युद्ध के परिवर्तित स्वरूप ने हमारे समक्ष शांति का महत्त्व उजागर किया। स्थिति यह हो गयी कि शान्ति बड़ी तेजी से सर्वोपरि मूल्य का पद ग्रहण करती गई। निशस्त्रीकरण का आरम्भ, विश्व नागरिकता का समर्थन तथा विश्व संस्थाओं आदि के विकास ने इस संदर्भ में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। फलतः समकालीन या आधुनिक यथार्थवादियों ने यह महसूस किया कि राज्यों के आचरण का मुख्य तथ्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के अनुसार होना चाहिए। पर वे शक्ति की प्राथमिकता और महत्त्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक कोई आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम नहीं होती, तब तक हिंसा पर नियंत्रण रखने, विरोधों को शान्त करने या अराजक व्यवस्था में द्वन्द्व तथा सहयोग की स्थिति में शक्ति के घटक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे कहते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध कितने ही मधुर क्यों न हों, उनमें कभी न कभी मतभेद व संघर्ष उत्पन्न हो ही जाते हैं, चाहे सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक या सर्वाधिकारवादी (तानाशाही) हो। अराजक व्यवस्था के कारण भय, शंका, द्वेष तथा असुरक्षा उत्पन्न होती है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विभिन्न संरचनाओं के विश्लेषण द्वारा वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न आयामों या नियमों का निरूपण करते हैं।

लेकिन समकालीन या आधुनिक यथार्थवाद में भी रेमाँड आरों (Raymond Aron), रॉबर्ट गिल्पिन, स्टेनली हॉफमैन तथा जोजेफ ग्रीचो जैसे प्रमुख लोगों का एक अन्य समूह उभरा, जिन्होंने समकालीन यथार्थवाद को पूर्णतया संतोषजनक नहीं माना, क्योंकि उनके अनुसार राष्ट्रों का एकमात्र उद्देश्य असीमित लाभ प्राप्त करना होता है तथा सभी राष्ट्र असीमित तथा सापेक्ष लाभ दोनों में रुचि रखते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि का पालन आवश्यक मानते हैं।

इनके अतिरिक्त विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोणों से भिन्न विचार रखता है। उनका मानना है कि पूर्णतया युद्ध के साधन पर निर्भर रहकर कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के बारे में निश्चित नहीं रह सकता। राष्ट्रों को अपने हितों में समायोजन या मेल पैदा करने के उपाय खोजने की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय हितों का मेल अस्तित्व रक्षा के लिए एक निश्चित साधन है।

इस प्रकार यथार्थवादी दृष्टिकोण ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को सैद्धान्तिक एवं वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि प्रदान की। इसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवादी-कल्पनावादी पर्यावरण से मुक्ति दिलाकर, विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक आधार प्रस्तुत किया, जो सामान्य सिद्धान्त निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था।

यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाएँ

आधुनिक विश्व राजनीति के अध्ययन में यथार्थवाद राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी अवधारणाओं पर विशेष जोर देता है क्योंकि इन अवधारणाओं के बिना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का क्रमबद्ध अध्ययन असंभव है। इन अवधारणाओं को निम्न रूप में देखा जा सकता है:

राष्ट्रीय हित–प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह यथार्थ आज जितना सत्य है उतना ही उस समय भी सत्य था जब वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आयी थी। इसलिए मॉरगेन्थाउ

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

ने राष्ट्रहित को शक्ति कहकर पुकारा तथा राष्ट्रहित को प्रधानता प्रदान की। राजनीति का प्रमुख आधार उनके अनुसार राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है और इस हित की प्राप्ति के लिए शक्ति आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि शक्ति ही राजनीति का केन्द्रबिन्दु है। शक्ति और हित परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। मॉरगेन्थाउ राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित या निर्धारित अर्थ मानकर नहीं चलते। वे राष्ट्रीय हित को राष्ट्र की शक्ति की प्राप्ति के प्रयत्न के समान मानते हैं तथा कहते हैं, शक्ति का अर्थ है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर नियंत्रण बनाए रखना।

इस प्रकार राष्ट्रीय हित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक प्रमुख अवधारणा है। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही होती है और यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सदा प्रयत्नशील रहता है। अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना प्रत्येक राष्ट्र का सार्वभौमिक अधिकार है। प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हित के आधार पर ही अपने कार्य को न्यायसंगत बनाने का प्रयास करता है। प्रत्येक राष्ट्र का व्यवहार भी हमेशा उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होता है। मॉरगेन्थाउ के अनुसार यह केवल राजनीतिक आवश्यकता ही नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है कि वह दूसरे राष्ट्रों के साथ एक मार्गदर्शक, एक ही कार्य करने के नियम और एक ही विचार स्तर का राष्ट्रीय हित अपनाएँ।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक राष्ट्र का हित उसके भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार में ही निहित होता है। किसी देश की विदेश नीति तभी सफल हो सकती है, जबकि राष्ट्रहित ही उस नीति के एकमात्र निर्देशक हों, वरना उस नीति को अवश्य असफल होना है। मॉरगेन्थाउ राष्ट्रहित के संबंध में कहते हैं कि राष्ट्रहित का अर्थ बहुत व्यापक है और उसका स्वरूप उन बहुत-से सांस्कृतिक तत्त्वों पर निर्भर है जिनके अन्तर्गत किसी राज्य की विदेश नीति निर्धारित की जाती है। उन्होंने राष्ट्रहित के दो मुख्य पक्ष बतलाये हैं–एक है स्थिर स्थायी अथवा आवश्यक और दूसरा है अस्थिर, अस्थायी अथवा अनित्य। स्थिर पक्ष वह है जो प्रत्येक देश के लिए समान रूप से महत्त्वपूर्ण है और अस्थिर पक्ष वह है जिसका स्वरूप प्रत्येक देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।

राष्ट्र की अस्तित्व रक्षा राष्ट्रहित की न्यूनतम आवश्यकता है। यह अस्तित्व रक्षा ही राष्ट्रहित का स्थिर पक्ष है। अस्तित्व रक्षा राष्ट्रहित का स्थिर पक्ष इसलिए है कि प्रत्येक राज्य के शासक यह मानकर चलते हैं कि उनके देश की रक्षा केवल शक्ति द्वारा ही हो सकती है और अस्तित्व रक्षा के बिना उनका देश किसी भी दिशा में उन्नति नहीं कर सकता। परन्तु अस्थायी पक्ष का स्वरूप स्पष्ट रूप से पहचानना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि जनमत और हमारी राजनीतिक एवं नैतिक प्राथमिकताओं में परिवर्तन होने के साथ-साथ राष्ट्रहित के अस्थायी पहलु में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए विदेश नीति का यह प्रमुख कार्य है कि वह समय-समय पर राष्ट्र-हित के अस्थिर तत्त्व को स्पष्ट करती रहे और देश के भविष्य और वर्तमान लक्ष्यों की भी स्पष्ट व्याख्या करती रहे। भविष्य के लक्ष्य राष्ट्रहित के स्थिर तत्त्व द्वारा और वर्तमान लक्ष्य अस्थिर तत्त्व द्वारा पहचाने जा सकते हैं तथा दोनों लक्ष्यों के बीच भी परस्पर संबंध हमेशा बना रहता है। वर्तमान लक्ष्य का संबंध मौजूदा परिस्थितियों से होता है और वे परिस्थितियाँ स्वयं अस्तित्व रक्षा के लिए किये गए प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं और बदलती रहती हैं।

मॉरगेन्थाउ इस संबंध में कहते हैं कि अस्थिर पक्ष अक्सर बाहरी आवरण के भीतर रहता है। इस संबंध में वे विशेष आवरण का जिक्र करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आवरण किसी देश के उन अन्दरूनी गुटों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, जो अपने तुच्छ संकीर्ण हितों को राष्ट्रहित की संज्ञा देते हैं। राजकीय सत्ता प्राप्त करने के बाद यह गुट अपने निजी हितों को राष्ट्रहित कहकर जनता के समक्ष पेश करता है। कभी-कभी सत्ता से बाहर रहकर यह गुट विदेश नीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। द्वितीय आवरण विदेशी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप जन्म लेता है। यह प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप नीति-निर्माता किसी अन्य देश के दबाव में अपने देश का राष्ट्रहित निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना से भी राष्ट्रहित का सही रूप छिप जाता है।

NEERAJ PUBLICATIONS

इस प्रकार राष्ट्रहित का सही रूप उपराष्ट्रीय, अन्य राष्ट्रीय तथा अति राष्ट्रीय आवरण में ढक जाता है। इसलिए मॉरगेन्थाउ के अनुसार राष्ट्रनेताओं का प्रथम कर्त्तव्य है कि राष्ट्रहित के इन तीनों आवरणों को अवांछनीय प्रभाव से बचाए और यह निश्चय करें कि देश के विभिन्न लक्ष्यों में कौन-से प्राथमिक हैं तथा कौन-से द्वितीय। साथ ही उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी देश के पास समस्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन नहीं होते। इसलिए उन्हें अपने उपलब्ध साधनों का प्रयोग विवेक द्वारा करना चाहिए और इस प्रकार करना चाहिए कि प्राथमिक हितों की पूर्ति अधिक से अधिक की जा सके। लेकिन यह तभी संभव है जब राजनेताओं को स्थिर व अस्थिर तत्त्वों का पूरा ज्ञान हो। सामान्यत: यह देखा जाता है कि स्थिर तत्त्व अस्थिर तत्त्व पर प्रभावी हो जाता है और विदेश नीति के प्रत्येक लक्ष्य का औचित्य स्थिर तत्त्वों के आधार पर तय किया जाता है। इसलिए मॉरगेन्थाउ दोनों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल प्रदान करते हैं।

राष्ट्रहित संबंधी अपने विचारों को मॉरगेन्थाउ नैतिकता से अलग रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि संसार में रहकर पाप एवं बुराई से बचकर रहना असंभव है, इसलिए हमें इस बात का

www.neerajbooks.com